भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1710
उत्तर दिनांक 29/07/2026 को दिया गया

रेयर अर्थ कॉरिडोर

1710. श्रीमती संजना जाटव
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) देश में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' के कार्यान्वयन में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) को सौंपी गई भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए आईआरईएल द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के माध्यम से किए गए निवेश और सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में इन पहलों के संभावित योगदान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) केंद्रीय बजट 2026-27 में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में समर्पित विरल मृदा कॉरिडोर स्थापित करने हेतु सहायता देने की घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुरूप, भारत सरकार के सभी हितधारक मंत्रालयों और चार राज्य सरकारों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया, जो इसके लिए दिशानिर्देश तैयार करेगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू), आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (आईआरईएल), गठित संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का एक सदस्य है।

(ख) व (ग) आईआरईएल ने वर्ष 2024 के दौरान रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए एक परियोजना - "विरल मृदा स्थायी चुंबक संयंत्र, विशाखापट्टनम" को पूरा किया है। इस परियोजना की लागत 196.50 करोड़ रुपए थी और इस परियोजना ने 65 लोगों के लिए रोजगार सृजित किया है।

(घ) आईआरईएल द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाएं वर्ष 2025 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सिंटरित विरल मृदा स्थायी चुंबकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगी।

*****